बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 235

तत्काल समाधान जरूरी

देश के राजनेताओं में आम जनता की समस्याओं को राजनीतिक मुद्दा बना देने की क्षमता है जिससे समस्या का समाधान असंभव सा हो जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि देश की राजधानी में पेयजल की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। इस रिपोर्ट ने भी एक नए राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है और अब ध्यान समस्या का समाधान तलाश करने से दूर हो चुका है। गत सप्ताह आई इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के 21 राज्यों की राजधानियों में नई दिल्ली का पेयजल सर्वाधिक असुरक्षित है। दिल्ली सभी 19 मानकों पर विफल रहा जबकि मुंबई (एक भी नाकामी नहीं), भुवनेश्वर और हैदराबाद (एक-एक कमी) के साथ शीर्ष तीन स्थानों पर रहे। किसी भी जवाबदेह राज्य प्रशासन के लिए यह रिपोर्ट कुछ गंभीर आत्मावलोकन के अवसर लेकर आती है। निश्चित रूप से यह प्रदेश की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) के लिए भी अच्छी बात नहीं है। आप के लिए तो यह रिपोर्ट खासतौर पर शर्मिंदा करने वाली है क्योंकि यह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 2015 के उस विवादास्पद कदम को खारिज करती है जिसके तहत उन्होंने नि:शुल्क या भारी रियायत पर पानी उपलब्ध कराने की बात कही थी। इसके विरोध में एक वरिष्ठ अफसरशाह ने इस्तीफा भी दिया था। इस वर्ष के आरंभ में प्रदेश सरकार ने पानी के बिल का पूरा बकाया माफ करने की घोषणा कर हालात और जटिल बना दिए।

वास्तव में बीते पांच वर्षों से दिल्ली सरकार नागरिकों को प्रदूषित पानी वितरित करती आई है। जल उपचार संयंत्रों में निवेश करना तथा जल संरक्षण के उपाय अपनाना कहीं अधिक सटीक हल है लेकिन शायद यह तीन महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनावों की दृष्टि से उपयुक्त न हो। परंतु जिस तरह अधिकांश राजनेता अपने ही बुने लोकलुभावन जाल में फंस जाते हैं, केजरीवाल ने भी आक्रामक तरीके से रिपोर्ट को नकारने का रुख अपनाया है। उन्होंने इस रिपोर्ट को गलत और राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने न केवल सरकार की मानक तय करने वाली संस्था के प्रति अविश्वास दर्शाया है बल्कि वह यह भी नहीं बता सके कि आखिर अन्य विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों की राजधानियों का प्रदर्शन दिल्ली से बेहतर कैसे है। बेहतर होता अगर वह मानक ब्यूरो की रिपोर्ट को स्वीकार कर लेते और प्रशासन के साथ मिलकर तंत्र की खामियां दूर करने की दिशा में प्रयास करते।

उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान भी हालात को संभाल नहीं पाए और उन्होंने एक चुनौती के माध्यम से पूरे प्रकरण का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया। पासवान ने अधिकारियों की एक संयुक्त टीम के माध्यम से दिल्ली के पेयजल की दोबारा जांच कराने की बात कही। यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसा करने की क्या आवश्यकता है। हालांकि केजरीवाल ने इसे स्वीकार करते हुए अपनी तरफ से प्रतिस्पर्धी चुनौती सामने रख दी है। यह विचित्र है कि दो ऐसे राजनेता जो इस समस्या को हल करने की स्थिति में हैं, वे इस प्रकार आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं जबकि दिल्ली के गरीब नागरिक गंदा और संक्रमित पानी इस्तेमाल करने को विवश हैं। अमीरों के पास जल उपचारित करने वाले उपकरण खरीदने की क्षमता है। विडंबना यह है कि कुछ महीनों में नेता इन्हीं गरीबों के पास वोट मांगने पहुंचेंगे। वायु प्रदूषण की तरह पानी की गुणवत्ता को लेकर छिड़ी राजनीतिक लड़ाई नेतृत्व के दिवालियेपन को ही दर्शाती है। पासवान शायद इस रिपोर्ट के आप की चुनावी संभावनाओं पर असर को देख रहे होंगे लेकिन जब उनकी ही सरकार के 2024 तक पूरे देश को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के वादे की बारी आती है तब उनको समग्रता में जोखिम का आकलन करना होगा। उन्हें पता चलेगा कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं।

अजय मोहंती

आरसेप को इनकार के बाद एशिया में भारत की भूमिका

आरसेप समझौते का हिस्सा बनने से भारत का इनकार एक ठोस वैश्विक विनिर्माण आधार बनने का मौका गंवाने जैसा है। इसके तमाम पहलुओं पर रोशनी डाल रही हैं **अनीता इंदर सिंह**

एशिया में भारत किस मुकाम पर खड़ा है? आसियान के एजेंडे में 2012 से ही शामिल क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसेप) का हिस्सा बनने से इनकार के बाद भारत की स्थिति में क्या कोई बदलाव आया है? एशिया-प्रशांत आर्थिक सम्मेलन (एपेक) और प्रशांत-पार समग्र एवं प्रगतिशील भागीदारी समझौता (सीपीटीपीपी) जैसे समूहों का हिस्सा नहीं होने से भारत के पास एशिया के आर्थिक भविष्य को परिभाषित करने वाले गुट को प्रभावित कर पाने का मौका पहले से ही नहीं है। जापान जैसे मित्र देश इसे लेकर फिक्रमंद हैं कि भारत की गैरमौजूदगी से चीन को आरसेप पर दबदबा बनाने और एशिया पर आर्थिक ताकत बनाए रखने की छूट मिल जाती है।

आरसेप को लेकर भारत का इनकार एक ठोस वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के गंवाए हुए मौकों में से एक को दर्शाता है। अर्थशास्त्र एवं सामरिक नीति के अंतर्संबद्ध होने के बाद कितने एशियाई देश ही अब एक वैश्विक शक्ति के तौर पर भारत की छवि को प्रसारित करेंगे? भारत का कहना है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आसियान को केंद्रीय भूमिका हासिल है। लेकिन इसी के साथ हिंद-प्रशांत के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की धुंधली अवधारणा से भी भारत इत्तफाक रखता नजर आ रहा है। उसने इस अवधारणा को हिंद महासागर से भी आगे पश्चिमी प्रशांत तक भारत के आर्थिक एवं रक्षा स्वरूप के विस्तार के तौर पर देखा है। हालांकि दक्षिण-पूर्व एवं पूर्व एशियाई समूहों में से किसी भी आर्थिक गुट से बाहर भारत के लिए ऐसा होना एक सपने जैसा ही है।

खुद अमेरिका ने भी हिंद-प्रशांत की संकल्पना को लेकर फैला संदेह दूर करने की कोशिश नहीं की है। ट्रंप की 2017 में घोषित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (एनएसएस) के मुताबिक, 'हिंद-प्रशांत' चीन के आर्थिक एवं सैन्य उत्थान को काबू में रखने की एक रणनीति है।

खुद ट्रंप ने वियतनाम के दा नांग में नवंबर 2017 में संपन्न एपेक के मुख्य कार्याधिकारियों (सीईओ) की बैठक में इस संकल्पना का ऐलान किया था। उस समय उन्होंने हिंद-प्रशांत के केंद्र में रहने के लिए वियतनाम की तारीफ की थी। (ध्यान रखें कि भारत एपेक समूह में भी शामिल नहीं है।) एनएसएस ने एपेक और आसियान को हिंद-प्रशांत का केंद्रीय तत्त्व बताया था। अगर भारत को अमेरिका एक अहम भूमिका निभाते हुए देखता है, तब भी उसने उस समय उसे हिंद-प्रशांत के केंद्र में नहीं रखा था।

असुविधाजनक हकीकत यह है कि भारत अपनी 'ऐक्ट ईस्ट' नीति के तहत जिन देशों के साथ संबंध सशक्त करने की मंशा रखता है, उनका समूह आसियान ट्रंप की हिंद-प्रशांत अवधारणा को नापसंद करता है। उनके लिए इस संकल्पना से 'एशिया' को बाहर रखना आसियान की केंद्रीयता को नजरअंदाज करता है लिहाजा वे सदस्य देशों पर असर डालने वाली किसी भी रणनीति पर सशंकित हैं।

आसियान ने गत जून में हिंद-प्रशांत को लेकर अपनी संकल्पना पेश की थी जिसमें एशिया-प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्रों को एक व्यापक आर्थिक चश्मे से देखने की बात कही गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही एशिया-प्रशांत का अमेरिका के दोस्त एवं सहयोगी बनने वाले दक्षिण-पूर्व एशियाई एवं पूर्व एशियाई देशों के लिए ऐतिहासिक अर्थ रहा है। आसियान की इस संकल्पना में भारत का उल्लेख नहीं है। असल में, अमेरिका एवं उसके एशियाई दोस्त लंबे समय से भारत को दक्षिण एशियाई देश ही मानते रहे हैं।

अमेरिका के सबसे सशक्त एशियाई सहयोगी जापान एवं दक्षिण कोरिया भी हिंद-प्रशांत पर बंटे हुए नजर आते हैं। वैसे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने ही इस शब्दावली को नाम दिया था लेकिन 1910-45 के दौरान कोरिया पर जापानी कब्जे के इतिहास और इस साल दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध छिड़ने से दक्षिण कोरिया को जापान पर भरोसा नहीं है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं भारत के साथ जापान को जोड़ने की जापानी पहल को समर्थन देने में उसे अधिक लाभ नहीं दिखता है। चीन के अग्रणी कारोबारी साझेदार होने और उत्तर कोरिया पर सर्वाधिक बढ़त रखने वाला देश होने के नाते दक्षिण कोरिया अमेरिका एवं चीन के बीच तनी हुई रस्सी पर चलता है।

यह सच है कि आसियान के देश सीमा का विस्तार करने की चीन की नीति को लेकर सशंकित रहते हैं लेकिन वे व्यापार एवं निवेश के लिए काफी हद तक उस पर निर्भर भी हैं। लिहाजा वे ऐसी स्थिति में नहीं फंसना चाहते हैं कि उन्हें अमेरिका एवं चीन में से किसी एक को चुनना पड़े। खुद भारत को भी अमेरिका के साथ मजबूत भागीदारी की चाहत एवं चीन के साथ रिश्ते को स्थायित्व देने की जरूरत के बीच संतुलन साधना होगा।

अर्थशास्त्र दक्षिण-पूर्व एवं पूर्व एशिया के साथ भारत के रिश्तों का एक अहम अवयव है। इन क्षेत्रों में भारत ने जापान, ऑस्ट्रेलिया, कई आसियान देशों और अमेरिका के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत बनाया है। लेकिन क्या इन रिश्तों ने भारत को प्रशांत क्षेत्र की एक ताकत बना दिया है? बमुश्किल ऐसा है। चीन एशिया की सबसे सशक्त सैन्य ताकत होने के साथ ही आसियान देशों का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। चीन का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) आकार करीब 15 लाख करोड़ डॉलर है जबकि भारत का आकार तीन लाख करोड़ डॉलर है। इसी तरह चीन का रक्षा व्यय करीब 250 अरब डॉलर है जबकि भारत रक्षा पर 66 अरब डॉलर खर्च करता है। आसियान के साथ चीन 288 अरब डॉलर का कारोबार है जबकि भारत का कारोबार 142 अरब डॉलर है। आसियान सदस्यों के उलट भारत ने चीन की अंतर-महाद्वीपीय निर्माण परियोजना बेल्ट एवं रोड पहल से खुद को अलग रखा हुआ है। अकेला यही तथ्य बता देता है कि भारत और आसियान देश चीन से निपटने के तरीके और आरसेप को लेकर क्यों असहमत हैं?

एक अन्य स्तर पर अर्थशास्त्र एवं सैन्य शक्ति का सम्मिलन यह बताता है कि भारत प्रशांत क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत का उस तरह से विस्तार करने में असमर्थ है जिस तरह से चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपना आर्थिक एवं सैन्य आभामंडल स्थापित किया है। जब चीन हिंद महासागर और भारत के पड़ोस में अपनी मौजूदगी बढ़ाता है तो भारत की आर्थिक एवं नौसैनिक शक्ति चीन का मुकाबला नहीं कर पाती है।

दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते आरसेप से अलग रहने का भारत का फैसला भी इस करार के समर्थकों को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। असल में, इस समझौते का हिस्सा बनने पर चीन के आयातित माल से भारतीय बाजार के पट जाने की आशंका ही यह दर्शाती है कि भारत अपनी आर्थिक कमजोरियों से सही तरह से नहीं निपट पाया है। यह उसके संरक्षणवादी रुख और लालफीताशाही पर लगाम लगाने में नाकामी के रूप में नजर आता है। क्या संरक्षणवादी भारत आसियान के अधिकांश देशों, जापान एवं दक्षिण कोरिया से कम जीडीपी होते हुए भी एक सशक्त एशियाई शक्ति के रूप में आश्वस्ति का भाव दिखा सकता है? और आर्थिक एवं सैन्य शक्ति के अंतर्संबद्ध होने से भारत को क्या वास्तव में एशिया में उदीयमान चीन के बरक्स एक संतुलन साधने वाली भूमिका में देखा जा सकता है? भारत को इन मुश्किल सवालों के जवाब तलाशने ही होंगे।

(लेखिका सेंटर फॉर पीस ऐंड कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्यूशन, नई दिल्ली की संस्थापक प्रोफेसर हैं)

मेंडलीफ की आवर्त सारणी 150वें साल में भी अनमोल

तकनीकी तंत्र

देवांग्शु दत्ता

मार्च 1869 में दिमित्री इवानोविच मेंडलीफ ने रशियन केमिकल सोसाइटी के समक्ष एक सारणी पेश की थी। इसे पहली आवर्त सारणी माना जाता है। पहली बार आवर्त सारणी तैयार होने के करीब 150 वर्ष बाद 21वीं सदी में भी इसमें नए तत्त्वों को जोड़ा गया है।

यह अविश्वसनीय उपलब्धि थी। मेंडलीफ ने वह सिद्धांत खोज निकाला था जिसे 'पीरियॉडिक लॉ' (आवर्त नियम) के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पाया था कि अपने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित अवयवों को नियमित अंतराल पर समान गुणों के आधार पर एक समूह में रखा जा सकता है।

मेंडलीफ की मूल सारणी में केवल 63 तत्त्व ही रखे गए थे। लेकिन उन्होंने यह कहा था कि भविष्य में नए तत्त्वों की तलाश होगी और उनके लिए उन्होंने सारणी में रिक्त स्थान रख छोड़ा था। उन्होंने नए तत्त्वों की रासायनिक संरचना के बारे में भी भविष्यवाणी की थी।

इस सारणी को परमाणु भार की गणना के आधार पर तैयार किया गया था जिसे सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। रसायन विज्ञानियों ने 19वीं सदी में समान संख्या वाले विभिन्न तत्त्वों के द्रव्यमान की गणना कर उनकी तुलना सबसे हल्के तत्त्व हाइड्रोजन के भार के अनुपात में की थी। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 दिया गया। इस तरह हाइड्रोजन की तुलना में 12 गुना भारी कार्बन का परमाणु भार 12 हो गया। कार्बन को परमाणु भार के लिए आधुनिक मानक माना जाता है।

बाद में हुई खोजें इस समझ की तरफ ले गईं कि अधिकांश हाइड्रोजन परमाणुओं में केवल एक प्रोटॉन होता है। अन्य तत्त्वों का परमाणु भार इससे अधिक होता है क्योंकि उनके परमाणु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है।

1930 के दशक में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की खोज होने के बाद तत्त्वों को परमाणु द्रव्यमान के बजाय प्रोटॉन की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाने लगा। इन दिनों, आवर्त सारणी में परमाणु संख्या का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हरेक परमाणु में मौजूद प्रोटॉन की संख्या है।

परमाणु संख्या हरेक तत्त्व के लिए अनूठी होती है क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होगी। एक ही तत्त्व के विभिन्न समस्थानिकों के लिए परमाणु भार अलग-अलग हो सकता है क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो सकती है। जैसे, हाइड्रोजन के प्राकृतिक तौर पर ज्ञात तीन समस्थानिक हैं। ये प्राकृतिक रूप से स्थायी हाइड्रोजन (प्रोटियम), ड्यूटीरियम और ट्राइटियम हैं जिनका सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान क्रमश: 1, 2 और 3 होता है। इन सभी समस्थानिकों का परमाणु भार 1 ही है।

कई तत्त्वों का प्रकृति में मिल पाना मुश्किल है क्योंकि वे रेडियोधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं। रेडियोधर्मी तत्त्व कणों का उत्सर्जन करते हैं और अधिक टिकाऊ तत्त्वों में परिवर्तित हो जाते हैं। कई रेडियोधर्मी तत्त्वों की संक्षिप्त अर्द्ध-आयु होने से वे क्षरण के चलते अधिक टिकाऊ तत्त्वों में बदल जाएंगे।

पृथ्वी 4.6 अरब वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में है। ऐसे में धरती पर अपेक्षाकृत संक्षिप्त अर्द्ध-आयु वाले कई तत्त्व मौजूद रहे हो सकते हैं लेकिन उनका इस कदर क्षरण हो चुका है कि अब उन्हें तलाशा नहीं जा सकता है। उच्च रेडियोधर्मिता वाले ऐसे तत्त्वों को अधिक स्थिर तत्त्वों के नाभिक में प्रोटॉन डालकर कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है।

उदाहरण के तौर पर मेटनेरियम एक कृत्रिम तत्त्व है जिसकी अर्द्ध-आयु महज 4.5 सेकंड ही है। इसे प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जा सकता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे समान तत्त्वों के कई समस्थानिकों को प्रयोगशालाओं में पल भर के लिए दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी अर्द्ध-आयु एक सेकंड से भी काफी कम होती है।

रसायनशास्त्रियों के नए तत्त्वों की खोज में लगने के साथ ही आवर्त सारणी में खाली स्थान धीरे-धीरे भरता चला गया। हाइड्रोजन (परमाणु संख्या-1) और प्लूटोनियम (94) के बीच के सभी तत्त्व धरती पर प्राकृतिक रूप में मौजूद हैं। लेकिन इनमें से कई तत्त्वों को पहले कृत्रिम तौर पर बनाया गया था और वे प्रकृति में बाद में खोजे गए।

सारणी में अमेरिसियम (परमाणु संख्या 95) से लेकर उसके बाद जोड़े गए सभी तत्त्वों को कृत्रिम रूप से बनाना है। संश्लेषण के माध्यम से तलाशा गया पहला तत्त्व टेक्नेटियम (परमाणु संख्या-43) था जिसे वर्ष 1937 में खोजा गया। मेंडलीफ ने इसके वजूद के बारे में अनुमान जताया था और उसे 'इकामैंगनीज' के नाम से संबोधित किया था। प्राकृतिक तौर पर भी यह पाया जाता है। पूरी तरह से कृत्रिम पहला तत्त्व क्यूरियम था जिसे 1944 में प्लूटोनियम पर अल्फा कणों की बारिश कर बनाया गया।

हाल ही में खोजा गया तत्त्व टेनेसाइन है जिसकी परमाणु संख्या 117 है। अमेरिका एवं रूस के संयुक्त शोध में यह तत्त्व वर्ष 2010 में खोजा गया। रूस के दुबना में स्थित ज्वाइंट इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम तत्त्व बर्केलियम पर कैल्सियम किरणों की बारिश की तो कैल्शियम के प्रोटॉन बर्केलियम के परमाणु से जुड़ गए। इसी तरह की बौछार से वर्ष 2002 में ओगेनेसॉन (परमाणु संख्या 118) को भी खोजा गया था।

परमाणु संख्या 92 से आगे वाले ट्रांस-यूरेनिक तत्त्वों के गुणों के बारे में बहुत कम जानकारी ही उपलब्ध हो सकी है। इसकी वजह यह है कि अधिकांश तत्त्व कृत्रिम हैं और उनकी अर्द्ध-आयु भी बहुत कम होती है। प्रयोगशालाओं में अध्ययन कर उनके रासायनिक गुणों के बारे में पता कर पाना मुश्किल है। इसी के साथ शोधकर्ता परमाणु संख्या 119 और उससे आगे के तत्त्व तलाशने की भी कोशिशों में लगे हुए हैं। इस तरह आवर्त सारणी अपने वजूद के 150वें साल में भी तत्त्वों के वर्गीकरण के लिए एक अनमोल संसाधन बनी हुई है।

कानाफूसी

बाबागीरी पर दें ध्यान

स्वयंभू बाबा और मध्य प्रदेश में नर्मदा-क्षिप्रा-मंदाकिनी नदी न्यास के चेयरमैन कंप्यूटर बाबा ने पिछले दिनों यह घोषणा करके सबको चकित कर दिया कि वह 2000 साधुओं का एक जत्था तैयार करेंगे जो मध्य प्रदेश में नदियों के किनारे अवैध रेत खनन रोकने का काम करेगा। बाबा ने कहा कि वह अपने कदमों से रेत माफिया को चौंका देंगे। उनकी योजना 250 से 300 साधुओं के जत्थे तैयार करने की थी लेकिन सरकार ने उनकी इस योजना के शुरू होने से पहले ही उस पर लगाम कस दी। प्रदेश के खनन मंत्री प्रदीप जयसवाल ने कहा कि कंप्यूटर बाबा एक धार्मिक व्यक्ति हैं और नदी न्यास के अध्यक्ष भी हैं लेकिन उनका खनिज और खनन विभाग से कोई लेनादेना नहीं है। जयसवाल ने कहा कि बेहतर होगा अगर बाबा अपनी बाबागीरी पर ही ध्यान दें और सरकारी विभागों का काम सरकार पर ही छोड़ दें।

गुजराल की जन्मशताब्दी

पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की 100वीं वर्षगांठ आगामी 4 दिसंबर को है। उनके पुत्र नरेश गुजराल तथा शेष परिजन इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनैशनल सेंटर पर एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। नरेश गुजराल शिरोमणि अकाली दल से राज्य सभा सदस्य हैं जो भाजपा की साझेदार है। गुजराल का निधन सन 2012 में हुआ था। वह पहले कांग्रेस और उसके बाद जनता दल में थे। कार्यक्रम में जिन लोगों को बतौर वक्ता आमंत्रित किया गया है उनमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और कांग्रेस नेता कर्ण सिंह शामिल हैं। गुजराल की रुचि कूटनीति में थी और वह विदेश मंत्री भी रह चुके थे। ऐसे में इस अवसर पर देश की विदेश नीति पर एक चर्चा का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें चार पूर्व विदेश सचिव शिवशंकर मेनन, के रघुनाथ, कंवल सिब्बल और श्याम सरन हिस्सा लेंगे।

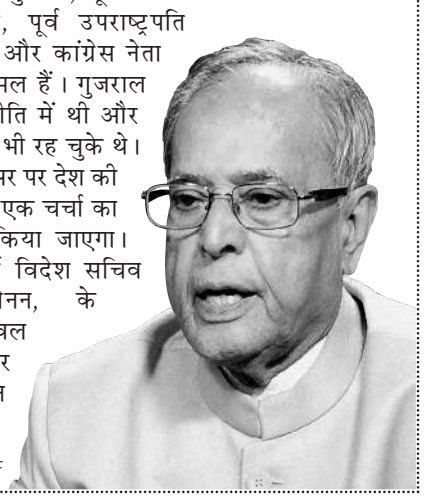

प्रणव मुखर्जी

आपका पक्ष

प्रकृति से लगाव ही बेहतर भविष्य देगा

राजस्थान में अबतक 17,000 प्रवासी पक्षियों की मौत हो चुकी है। राज्य में सांभर झील जयपुर, नागौर और अजमेर के कुछ जिलों में फैली है। यहां हर साल बड़ी तादाद में दूसरे देशों से पक्षी आते हैं। वे अपने लायक अनुकूल वातावरण खोज लेते हैं और तय समय में अपने मूल आवास से विचरण करते हैं। इस समय विदेशी पक्षियों की अनेक प्रजातियां देश की कई जगहों पर प्रवास करने आती हैं। लेकिन यहां का वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका है कि बड़ी संख्या में उनकी मौत हो रही है। मौत का कारण बोटुलिज्म बताया जा रहा है। इससे मृत पक्षियों के जीवाणुओं से पक्षियों में अपंगता पनपती है जिससे उनकी मौत हो जाती है। पिछले एक सप्ताह में करीब 17 हजार पक्षियों का मर जाना बड़ी त्रासदी का संकेत है। हमें इस समय वातावरण को अनुकूल बनाने की दिशा में काम करने की जरूरत है। आधुनिकता की भागदौड़ में हम वातावरण को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारी जीवन शैली दुनिया को विनाश की ओर ले जा रही है। रोजाना इस्तेमाल में आने वाले कई उत्पादों से धरती प्रदूषित हो रही है। हमें आधुनिकता के साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों में जीवन जीने की आदत डालनी चाहिए।

राजस्थान की सांभर झील में लगभग 17 हजार प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है

प्रकृति के साथ जीने में न तो वातावरण प्रदूषित होगा, न ही मनुष्यों में कोई बीमारी आएगी। देश में आदिवासी समाज प्रकृति के साथ जीवन व्यतीत करता है जिसे कुछ सभ्य लोग उन्हें असभ्य कहते हैं। अत: हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रकृति से लगाव रखना होगा। अपने घरों में पेड़ पौधे लगाने होंगे। एसी, फ्रिज, कार और अन्य संसाधनों के बदले प्राकृतिक उपाय अपनाने होंगे। तभी इस धरती को हम अपने भविष्य के लिए बेहतर बना सकेंगे।

अरुण कुमार, जयपुर

संसद का 250वें सत्र में हो सुचारु काम

संसद का 250वां सत्र सोमवार को शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में दो दलों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) तथा बीजू जनता दल (बीजद) की तारीफ की। मोदी ने कहा कि दोनों दल किसी मुद्दे पर विरोध करने के लिए अध्यक्ष के आसन के समीप नहीं जाते हैं। यह एक सराहनीय कदम है, इससे संसद की कार्यवाही में बाधा नहीं पहुंचती है। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि ऐसे प्रयास सभी दलों को करना चाहिए जिससे संसद सुचारु रूप से चल सके। देश की संसद में विभिन्न मुद्दों पर बहस होती है लेकिन विरोध के चलते काफी समय बरबाद हो जाता है। संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए नेताओं को विरोध करने का सही तरीका अपनाना चाहिए जिससे संसद का वक्त खराब न हो और सार्थक चर्चा होती रहे। इससे देश के विभिन्न मुद्दों की सार्थक चर्चा होगी तथा उसका हल निकल सकेगा। संसद में एक दिन में हजारों रुपये खर्च होते हैं। यह पैसा आम जनता के टैक्स से आता है। टैक्स का पैसा ऐसे बरबाद करना ठीक नहीं है। देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे में संसद को इन समस्याओं का हल निकालना चाहिए।

मनीष कुमार, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।